गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 188
दि. 09.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

बिहार में एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है : सीएम योगी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए रैली की। उन्होंने मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा की। साथ ही कांग्रेस औरआरजेडी पर जमकर हमला बोला।

(जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार ने पहले चरण के मतदान में ही यह संकेत दे दिया है कि अब लालटेन की धुंधली रोशनी नहीं, बल्कि एनडीए की एलईडी लाइट में जगमगाता बिहार चाहिए। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे, तो फिर एक बार एनडीए की सुशासन, विकास और सुरक्षा की सरकार बनने जा रही है। बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए।

'यह पाप कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों का है'

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह वही धरती है जिसने माँ जानकी को शरण दी, जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया और जिसने भारत को स्वतंत्रता की दिशा दिखाई। सत्याग्रह की यह भूमि राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र के आग्रह से भी कभी पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि यह धरती नालंदा की ज्ञानगंगा की धारा रही है, आचार्य चाणक्य, आर्यभट्ट, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसी विभूतियों की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि फिर भी बिहार साक्षरता में पिछड़ गया, यह पाप कांग्रेस और आरजेडी की सरकारों का है। उन्होंने बिहार की मेधा और प्रतिभा का शोषण किया, अपने स्वार्थ के लिए बिहार को पिछड़ा बनाए रखा।

एनडीए का सुशासन ही बिहार के विकास की राह

सीएम योगी सीएम योगी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को स्थिरता, सुरक्षा और सुशासन दिया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सड़कों का जाल है, रेल, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे और मेट्रो जैसी सुविधाएं हैं। अब यहां आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, एम्स और मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला खुल रही है। उन्होंने कहा कि निवेश वहीं आता है जहां सुरक्षा होती है। अगर अपराधी जीतेगा तो निवेश भाग जाएगा, सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और नौजवान फिर पलायन करेगा। बिहार में अपराधी नहीं, विकास की सरकार चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने अपने तीखे अंदाज में कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफियाओं की छाती रौंदी है। जब बुलडोजर चलता है तो माफिया की हड्डी और पसली एक हो जाती है। यूपी में अब अपराधी पस्त है और नौजवान मस्त है। उन्होंने कहा कि बिहार को भी अपराधियों से मुक्त रखकर सुशासन की राह पर आगे बढ़ाना है।

राम तो हुए ही नहीं— यह कहने वाले अब जवाब दें

योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाया था। समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोली चलवाई। उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद रामभक्तों ने कहा था, 'रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे' और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राममंदिर बनकर तैयार है। सीएम योगी ने बताया कि अयोध्या में अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट, निषादराज के नाम पर यात्री विश्रामालय और माता शबरी रसोई स्थापित की गई है। वहीं, राम मंदिर परिसर में जटायु और गिलहरी की प्रतिमाएं भारत की कृतज्ञता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, तो सीतामढ़ी में माँ जानकी का मंदिर भी एनडीए सरकार बना रही है। अयोध्या से सीतामढ़ी को जोड़ने वाला राम जानकी मार्ग 6155 करोड़ रुपए से स्वीकृत हो चुका है और काम शुरू हो गया है। अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे भी मोतिहारी होते हुए जाएगा, जो आर्थिक कॉरिडोर का काम करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बना मजबूत राष्ट्र

सीएम योगी सीएम योगी ने कहा कि आज भारत मजबूर नहीं, मजबूत है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, वह अब यमराज की टिकट लेकर जाएगा। मार्च 2026 तक नक्सलवाद और माओवाद की कमर तोड़ने का संकल्प लिया गया है और उनका जहन्नुम जाने का टिकट अब पक्का हो चुका है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को सम्मान, सुरक्षा और अवसर दिए हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना से रसोई गैस और 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर के कनेक्शन लिए 50,000 रुपए देने पड़ते थे और लाइन में लाठी मिलती थी। पीएम मोदी ने गरीब मां-बहनों को रसोई गैस से सम्मान दिया है।

अपराधी नहीं, एनडीए प्रत्याशी प्रमोद कुमार को दें आशीर्वाद

सीएम योगी महागठबंधन प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसी सभी धाराओं में 28 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अगर ऐसे अपराधी उत्तर प्रदेश में होते, तो जेल से बाहर नहीं निकल पाते।

तेज प्रताप यादव को मिली + सिक्योरिटी, बिहार चुनाव के बीच में लालू के लाल पर गृह मंत्रालय क्यों हुआ मेहरबान

केंद्र सरकार ने जन शक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले उन्हें मोदी सरकार की ओर से वाई प्लस (Y+) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) तेज प्रताप यादव की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा।

हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को तेज प्रताप यादव की सुरक्षा स्थिति पर एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने यह निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में रविवार को जूनागढ से राज्यव्यापी पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च – पदयात्रा का आयोजन तथा आत्मनिर्भर भारत की शपथ ली जाएगी

(जीएनएस)।

गांधीनगर, 08 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल 9 नवंबर रविवार को यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाली राज्यव्यापी पदयात्रा का जूनागढ से प्रारंभ कराएंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य सरकार के खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के विभाग तथा जूनागढ जिला प्रशासन के

उपक्रम से इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1947 में 9 नवंबर को जूनागढ नवाबी शासन से स्वतंत्र हुआ था और उसका भारत में विलय हुआ था, जिसे जूनागढ मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभभाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान से जूनागढ का भारत में विलय कराए जाने के इस यादगार दिवस के समय ही इस वर्ष मनाई जा रही सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में यूनिटी मार्च के हिस्से के रूप में इस पदयात्रा का आयोजन विशेष महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल रविवार सुबह 7 बजे इस पदयात्रा का प्रारंभ कराएंगे। इस अवसर पर जूनागढ जिला प्रभारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. प्रद्युमनभाई वाजा, जिला सह प्रभारी विधि राज्य मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, जूनागढ के महापौर श्री धर्मेश पोशिया, विधायक तथा पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज के आठवें 180वें उपवास पारण समारोह को संबोधित किया

- **उपराष्ट्रपति ने शांति और वैश्विक मान्यता में जैन धर्म के योगदान पर प्रकाश डाला**
- **उपराष्ट्रपति ने तमिल साहित्य और संस्कृति पर ऐतिहासिक जैन प्रभाव पर प्रकाश डाला**
- **जड़ों की ओर लौटना: उपराष्ट्रपति ने भारतीय मूल्यों, परिवार और संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया**
- **उपराष्ट्रपति ने भारतीय विरासत के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की**
- **ज्ञान भारतम मिशन और प्राकृत के लिए शास्त्रीय भाषा मान्यता भारत की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करती है**

(जीएनएस)।

श्री हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज जी के आठवें 180 उपवास पारण समारोह में भाग लिया।

सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने दिव्यतपस्वी आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज के पवित्र महापर्ण में भाग लेने के लिए बहुत आभार जताया।

दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक, जैन धर्म के गहन योगदान पर रोशनी डालते हुए, श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इसकी शिक्षाओं – अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद – ने

भारत और विश्व पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी द्वारा अपनाई गई अहिंसा, वैश्विक शांति आंदोलनों को प्रेरित करती रही है। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शाकाहार, पशुओं के प्रति करुणा और सतत जीवन शैली के जैन सिद्धांतों को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के एक आदर्श के रूप में दुनिया भर में मान्यता मिली है।

अपनी व्यक्तिगत यात्रा को याद करते हुए, श्री राधाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने 25 वर्ष पहले काशी की यात्रा के बाद शाकाहार अपनाया था, और यह पाया था कि इससे विनम्रता, परिपक्वता और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना विकसित होती है।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्राकृत को 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा देने तथा ज्ञानभारतम मिशन जैसी पहलों के माध्यम से जैन पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए सरकार के प्रयासों की प्रशंसा की।

उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु में जैन धर्म की ऐतिहासिक व्यापकता और तमिल संस्कृति पर इसके व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने संगम और संगमोत्तर काल के दौरान तमिल साहित्य में जैन धर्म के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया और इलांगो आदिगल द्वारा रचित शिलप्पादिकारम और कोंगु वेलिर द्वारा रचित पेरुंगथाई जैसी शास्त्रीय रचनाओं का हवाला दिया, जो अहिंसा, सत्य और त्याग के दार्शनिक और नैतिक आदर्शों को दर्शाती हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि तिरुक्कुरल और संगम साहित्य जैसे ग्रंथों पर जैन प्रभाव है। श्री राधाकृष्णन ने तमिलनाडु भर में कई जैन मठों की उपस्थिति पर प्रकाश डाला, जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के केंद्र रहे हैं।

श्री राधाकृष्णन ने आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सच्ची शक्ति धन या पद में नहीं, बल्कि संयम, करुणा और अनुशासन में निहित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आचार्य जी का "संस्कृति बचाओ, परिवार बचाओ, राष्ट्र निर्माण" अभियान समाज को मूल्यों को बनाए रखने, परिवारों को मजबूत बनाने और एक सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करता है।

आचार्य हंसरत्न सूरीश्वरजी महाराज एक श्रद्धेय जैन मुनि हैं जो अपनी आध्यात्मिक साधना और दीर्घकालिक तप साधना के लिए जाने जाते हैं।

श्री पीयूष गोयल मेलबर्न के दौरे पर, भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए वार्ता की प्रगति की समीक्षा के लिए द्विपक्षीय बैठकें कीं

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल 8 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के व्यापार एवं पर्यटन मंत्री सीनेटर माननीय डॉन फैरेल और कौशल एवं प्रशिक्षण मंत्री एंड्रयू जाइल्स के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। इन रचनात्मक चचाओं में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें एक महत्वाकांक्षी और संतुलित भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) भी शामिल है।

बैठक के दौरान, मंत्रियों ने सीईसीए वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में वस्तुओं व सेवाओं में कारोबार, निवेश और पारस्परिक रूप से लाभकारी

सहयोग समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा हुई।

वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार 24.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत के निर्यात में 2023-24 में 14% और 2024-25 में 8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

दोनों पक्षों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए), जो दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, की नींव पर एक संतुलित और पारस्परिक आधार पर लाभकारी सीईसीए को जल्दी पूरा करने की दिशा में रचनात्मक रूप से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

श्री पीयूष गोयल ने मंत्री फैरेल और मंत्री जाइल्स के साथ भारतीय प्रवासी समुदाय के चुनिंदा व्यावसायिक प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। इस बातचीत में मजबूत व्यावसायिक संबंधों के अवसरों पर ध्यान डाला गया और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में समुदाय की भूमिका पर जोर दिया गया।

रक्षा मंत्री नई दिल्ली में 16 डीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे

(जीएनएस)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 10 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। उन्होंने वर्ष 2025 को 'सुधारों का वर्ष' घोषित करते हुए डीपीएसयू से नई प्रौद्योगिकियों के विकास, निर्यात वृद्धि और स्वदेशीकरण को गति देने पर विशेष जोर दिया था। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रक्षा मंत्री ने डीपीएसयू को अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने और नवाचार के लिए श्रमबल को सशक्त बनाने का आ'ान किया।

सभी डीपीएसयू ने इस सिलसिले में आगामी पांच वर्षों के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास रोडमैप तैयार कर लिए हैं। पिछले दस वर्षों में, 16 डीपीएसयू ने अनुसंधान एवं विकास में कुल 30,952 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब अगले पांच वर्षों में 32,766 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ अनुसंधान एवं विकास की गति को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां पहले के दशक में अधिकांश निवेश पारंपरिक डीपीएसयू विशेष रूप से हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) द्वारा किया गया था, वहीं अब अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान सभी डीपीएसयू में समान रूप से केंद्रित हो गया है। आगामी पांच वर्षों में, आयुध निमार्णी बोर्ड के निगमीकरण से गठित सात नए डीपीएसयू अनुसंधान एवं विकास में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे, जबकि रक्षा शिपयार्ड भी 1,300 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजना बना रहे हैं।

इस कार्यक्रम के दौरान पिछले दस वर्षों में पूर्ण की गई विकास एवं अनुसंधान परियोजनाओं का संकलन प्रस्तुत किया जाएगा, साथ ही आगामी पांच वर्षों के लिए तैयार की गई नई कार्ययोजना भी जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की नई अनुसंधान एवं विकास नियमावली का अनावरण किया जाएगा, जो इन प्रक्रियाओं में अधिक लचीलापन, तेजी, जोखिम मूल्यांकन और संसाधन आवंटन की दक्षता सुनिश्चित करेगी।

रक्षा मंत्री 'स्वयं' शीर्षक से अक्षय ऊर्जा पर एक विशेष रिपोर्ट भी जारी करेंगे। यह रिपोर्ट रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में तैयार की गई है और इसमें सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) द्वारा अपनाई गई ऊर्जा दक्षता एवं अक्षय ऊर्जा से संबंधित सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का व्यापक संकलन प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय रूप से, वर्ष 2024-25 में डीपीएसयू का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। इस अवधि में डीपीएसयू ने कुल 1.08 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया, जो 2023-24 की तुलना में 15.4% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके साथ ही, कर-पश्चात लाभ बढ़कर 20,021 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.5% अधिक है।

विशेष रूप से, 2024-25 में

सम्पादकीय

ममदानी की जीत उनकी सुविचारित मुहिम की अधिक जीत

अमेरिका में इस साल यानी 2025 में दो ऐसे चुनाव हुए हैं जिनका असर पूरी दुनिया में पड़ा है। पहला 20 जनवरी को हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दूसरा चुनाव 4 नवम्बर को हुआ जब जोहरान ममदानी ने न्यूयार्व सिटी के मेयर का चुनाव जीता है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं था। कई मामलों में यह ऐतिहासिक चुनाव था। पहली बार 1892 के बाद से न्यूयार्व के सबसे युवा मेयर जोहरान ममदानी की जीत हुई है। वो न्यूयार्व सिटी के पहले मुस्लिम मेयर भी होंगे। उन्होंने पिछले साल ही चुनावी मैदान में पांव रखा था। उस समय उनके पास न तो कोई बड़ी पहचान थी, न ही बहुत सारे पैसे और न ही पार्टी का समर्थन था। यही वजह है कि उनकी एंड्रयू वुओमो और रिपब्लिक उम्मीदवार कार्टिस स्लिवा पर मिली जीत न केवल असाधारण थी पर कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। ममदानी युवा और करिश्माई हैं।

प्री चाइल्ड केयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के विस्तार और प्री मार्वेट सिस्टम में सरकारी दखल जैसे वामपंथी मुद्दों का समर्थन किया। न्यूयार्व शहर में करीब 48 फीसदी ईसाई और 11 फीसदी यहूदी हैं। यहां मुस्लिम भी नौ फीसदी हैं जो अमेरिका में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। कहा जाता है कि 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया की विरासत से यह शहर अब तक उभर नहीं सका है। यहां आज तक कोई मुस्लिम मेयर रहा भी नहीं।

इसके बावजूद अगर ममदानी को जीत मिली है तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि उनकी सुविचारित मुहिम की जीत अधिक लगती है। 34 साल के जिस युवा को उसके कम अनुभव की वजह से पहले चुनावी लड़ाई में कमजोर माना जा रहा था, बाद में वही सबसे अहम पैक्टर साबित हुआ। उनकी खासियत रही जनता से जुड़ाव। उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च करने की बजाए सीधे लोगों से संवाद किया। आम शहरों की समस्याओं को समझा और कई ऐसे वादे किए जो न्यूयार्व के नागरिकों को समझ आ गए, भा गए। ममदानी ने अपने चुनावी अभियान के दौरान भी मैनहैटन और न्यूयार्व सिटी के रहने वाले बड़े कार्पोरेट और कारोबारियों की कड़ी आलोचना की थी। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और तमाम उद्योगपतियों ने ममदानी का जमकर विरोध भी किया। ट्रंप ने धमकी भी दे डाली कि अगर ममदानी जीते तो वो उसकी पंडिंग बंद कर देंगे। उनकी मुस्लिम होने पर भी आलोचना की गई पर ममदानी ने खुलकर स्वीकार किया कि वह एक मुसलमान हैं और इस पर उन्हें गर्व है। इसलिए तमाम इस्लामिक दुनिया में उनकी जीत को एक नए युग का आगाज माना जा रहा है। वह न केवल ट्रंप के लिए सिरदर्द बन सकते हैं बल्कि नेतन्याहू को तो अगर वह न्यूयार्व आए तो उन्हें गिरफ्तार करने की भी धमकी वह दे चुके हैं। वह हमारे प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर चुके हैं और 2002 गुजरात दंगों को याद कराते रहते हैं। हालांकि जीतने के बाद अपने पहले भाषण में ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू को याद किया। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा, मैं जवाहर लाल नेहरू के शब्दों के बारे में सोचता हूं। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। आज रात हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

गुजरात आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट : आदिवासी समुदाय के आनुवंशिक रोगों की पहचान होने से किफायती निदान पद्धति का विकास होगा, 1 लाख रुपए के बजाय केवल 1000-1500 रुपए में होगा परीक्षण

गुजरात की अत्याधुनिक जीनोम सुविधा: 48 से 72 घंटे में होती है 25-50 नमूनों की सीक्वेंसिंग

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध

गांधीनगर, 08 नवंबर (जीएनएस)। गुजरात ने आदिवासी लोक नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 2025 को 'जनजातीय गौरव वर्ष' के रूप में मनाने का संकल्प किया है। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज की अस्मिता, आत्मसम्मान और बहादुरी के प्रतीक हैं, उनके सम्मान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस की पहल शुरू की है। श्री मोदी दृढ़तापूर्वक यह मानते हैं कि जब हमारे आदिवासी समुदाय समृद्ध होंगे, तो भारत भी समृद्ध होगा। उनके इस विजन का अनुसरण करते हुए गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गुजरात के आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने को प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप गुजरात, भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने आदिवासी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापक जीनोम सीक्वेंसिंग (अनुक्रमण) प्रोजेक्ट शुरू किया है।

जीनोम सीक्वेंसिंग और आदिवासी समुदाय के लिए इसका महत्व

शरीर की कोशिकाओं के अंदर मौजूद आनुवंशिक सामग्री को जीनोम कहा जाता है। कोशिका के अंदर जीन

का सटीक स्थान और उसकी रचना को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। यह जीनोम में होने वाले परिवर्तन के बारे में बताता है। गुजरात की आदिवासी आबादी लंबे समय से थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी आनुवंशिक बीमारियों से जूझ रही है। कुछ आनुवंशिक बीमारियां ऐसी होती हैं, जिनके बारे में आखिरी स्टेज तक पता नहीं चल पाता, जिससे उपचार और अधिक जटिल हो जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से वैज्ञानिक म्यूटेशन (परिवर्तनों) का पता लगा सकते हैं, कम लागत वाले डायग्नोस्टिक पैनल बना सकते हैं, और आईवीएफ प्रक्रियाओं के दौरान प्रसवपूर्व या फिर भ्रूण-स्तरीय परीक्षण भी कर सकते हैं।

जीनोम मैपिंग के जरिए आदिवासी समुदायों के स्वास्थ्य में सुधार का संकल्प

यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों का स्वास्थ्य कल्याण सुनिश्चित करते हुए बेहतर स्वास्थ्य-उन्मुख योजनाएं बनाने में मदद करेगा। इससे बीमारियों का पता लगाने, कुपोषण और एनीमिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने तथा सिकल सेल एनीमिया एवं ग्लूकोज-6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज (जी6पीडी) की कमी जैसे आनुवंशिक विकारों का शीघ्र निदान संभव होगा।

उदाहरण के लिए, यदि माता और पिता, दोनों में बीटा-ग्लोबिन जीन (जिसे वाहक कहा जाता है) की एक म्यूटेटेड कॉपी है, तो इस बात की 25 फीसदी संभावना है कि उनके बच्चे को दोनों म्यूटेटेड कॉपियां विरासत में मिलेगी, जिसके चलते सिकल सेल रोग विकसित होगा। जीनोम मैपिंग के माध्यम से ऐसे वाहकों की शीघ्र पहचान की जा सकती है, जिससे रोग के बारे में शीघ्र पता लगाया जा सके और निवारक उपाय किए जा सकें। इससे समुदाय के आनुवंशिक लक्षणों के अनुसार डीएनए परीक्षण तैयार किया जा सकता है।

ये परीक्षण केवल संबंधित समुदाय में आम तौर पर होने वाले जीन परितवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसका खर्च केवल 1000 से 1500 रुपए तक होता है। इसकी तुलना में, संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग व्यक्ति के सभी जीनों की पहचान करता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है और एक्सोम सीक्वेंसिंग केवल जीन के कोडिंग हिस्सों को पढ़ता है, जिसमें प्रति नमूना लगभग 18,000 से 20,000 रुपए का खर्च होता है। इस प्रकार, समुदाय-विशिष्ट परीक्षण ज्यादा व्यावहारिक और कम खर्चीले होते हैं।

गुजरात जीनोम सीक्वेंसिग प्रोजेक्ट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने विशेष आदिवासी समुदायों के लिए बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (जीबीआरसी) के नेतृत्व में यह प्रोजेक्ट आदिवासी समुदायों के आनुवंशिक खाके (जेनेटिक ब्लूप्रिंट) का अध्ययन करके रोग के परीक्षण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है। उल्लेखनीय है कि जीनोम इंडिया पहल के तहत कार्यरत जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट यह समझने का प्रयास करता है कि आखिर क्यों आदिवासी समुदायों में आनुवंशिक विकृतियां बढ़ रही हैं, जो अक्सर अंतर्विवाह (अपने ही समूह में विवाह) और सीमित आनुवंशिक विविधता के कारण होते हैं।

11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों के डीएनए नमूने एकत्र किए जाएंगे

गुजरात में जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत शोधकर्ता 11 जिलों के 31 आदिवासी समुदायों में से डीएनए के नमूने एकत्र कर एक डेटाबेस बना रहे हैं, जो इन समूहों में आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार के तरीकों को सुधारने में मदद करेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, गुजरात सरकार ने एक व्यापक जीनोम डेटाबेस बनाने और मौजूदा डेटा अंतराल को पाटने के लिए 'आदिवासी आबादी के लिए रेफरेंस जीनोम डेटाबेस का निर्माण' प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के सहयोग से चलाय जा रहा है।

आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के लिए जीनोम विज्ञान का उपयोग करने में गुजरात अग्रणी

गुजरात में जीनोम अनुसंधान को गति देने के लिए जीबीआरसी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें लॉन्ग-रीड सीक्वेंसर सहित तीन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीनें शामिल हैं, जो एक समय में 5000-10,000 बेस पेयर (मूल जोड़े) का विश्लेषण कर सकती है, जिससे वैज्ञानिकों को जटिल आनुवंशिक बदलावों का पता लगाने में मदद मिलती है। इन मशीनों का उपयोग पहले कोविड-19 के दौरान किया जाता था, लेकिन अब इनका उपयोग व्यापक जीनोम अनुसंधान के लिए किया जा रहा है।

गुजरात में, प्रत्येक सीक्वेंसिंग बैच 25-50 मानव जीनोम की सीक्वेंसिंग कर सकता है, इसके परिणाम 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाते हैं। जीबीआरसी ने लागत प्रबंधन और स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके प्रति नमूना खर्च 85,000 रुपए से घटाकर लगभग 60,000 रुपए कर दिया है। यह अनुसंधान डॉक्टरों को सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी उपचार प्रदान करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि आदिवासी समुदाय को आधुनिक जीनोम विज्ञान का लाभ मिले।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस : भारत की विधिक सहायता एवं जागरूकता पहल

9 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है,

जिसके कारण जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने वाले संगठनों की स्थापना हुई।

(जीएनएस)। मुख्य बातें भारत की कानूनी सहायता प्रणाली 44.22 लाख लोगों (2022-25) तक पहुंच चुकी है और लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ मामलों का समाधान किया गया है।

2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का समाधान किया गया।

लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फरवरी, 2025 तक) को दिशा योजना के माध्यम से मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क सेवाएं और कानूनी प्रतिनिधित्व एवं जागरूकता प्रदान की गई।

परिचय

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और कानून के तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है। फिर भी, कई लोग अशिक्षा, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं, अपराध या आर्थिक तंगी व अन्य बाधाओं के कारण कानूनी सेवाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। चूंकि यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था, इसलिए इसके कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के क्रम में, इस दिन, देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरणों के अलावा, फास्ट-ट्रैक और अन्य विशेष अदालतें अदालती मामलों में तेजी लाने में मदद करती हैं, वहीं, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण पहल और आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय को अधिक सुलभ और सस्ता बनाता है।

विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने यह सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विधिक सहायता संगठनों की स्थापना की कि आर्थिक या अन्य बाधाओं से जूझ रहे किसी भी नागरिक को न्याय पाने के समान अवसर से वंचित न किया जाए।

इस अधिनियम ने निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित कीः

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में)

अ कानूनी सहायता केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित की जाती है और तीन-स्तरीय वित्त पोषण संरचना के माध्यम से अनुदान दिया जाता हैः

राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष के माध्यम से केंद्रीय प्राधिकरण को केंद्रीय वित्त पोषण या दान

राज्य कानूनी सहायता कोष के माध्यम से राज्य प्राधिकरण को केंद्र या राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य योगदान

जिला कानूनी सहायता कोष के माध्यम से जिला प्राधिकरण को राज्य सरकार का वित्त पोषण या अन्य दान

पिछले तीन वर्षों में निःशुल्क कानूनी सहायता का लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दी गई कानूनी सहायता और सलाह से 44.22 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।

लोक अदालत

इस अधिनियम ने लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की, जो उपरोक्त विधिक प्राधिकारियों द्वारा आयोजित वैकल्पिक विवाद निवारण मंच हैं। ये मंच लंबित विवादों या मामलों या मुकदमे-पूर्व चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा करते हैं। 2022-23 से 2024-25 तक राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली (एलएडीसीएस) योजना

एनएएलएसए द्वारा शुरू की गई एलएडीसीएस योजना, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को आपराधिक मामलों में निःशुल्क कानूनी बचाव प्रदान करती है।

30 सितंबर, 2025 तक, 668 जिलों में एक कार्यशील एलएडीसीएस कार्यालय है।

2023-24 से 2025-26 (सितंबर, 2025 तक) तक एलएडीसी द्वारा सौंपे गए 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए एलएडीसी योजना का स्वीकृत वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये है।[11]

न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना

आधुनिक तकनीक लोगों को न्याय व्यवस्था तक आसानी से और किफायती पहुंच बनाने में भी मदद कर रही है। 2021-2026 तक लागू की गई दिशा योजना के माध्यम से लगभग 2.10 करोड़ लोगों (28 फरवरी, 2025 तक) को मुकदमेबाजी से पहले सलाह, निःशुल्क सेवाएं, और कानूनी प्रतिनिधित्व व जागरूकता प्रदान की गई। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका परिव्यय 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

बहुत से लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं। नालसा बच्चों, मजदूरों, आपदा पीड़ितों और समाज के अन्य हाशिए पर पड़े वर्गों से संबंधित कानूनों पर विभिन्न कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

अधिकारी सरल भाषा में पुस्तिकाएँ और पैम्फलेट भी तैयार करते हैं, जिन्हें लोगों में वितरित किया जाता है। 2022-23 से 2024-25 तक, विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने इनमें भाग लिया।

न्याय विभाग, दिशा के अंतर्गत कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (छछछअढ) चलाता है। सिक्किम राज्य महिला आयोग और अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रछरअ) जैसी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन एजेंसियाँ इस कार्यक्रम का संचालन करती हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से, विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों की 22 अनुसूचित भाषाओं और बोलियों में संचार सामग्री विकसित की है।

दूरदर्शन ने भी मंत्रालय के साथ सहयोग किया और छह भाषाओं में 56 कानूनी जागरूकता टीवी कार्यक्रम प्रसारित किए, जिनकी पहुंच 70.70 लाख से ज्यादा लोगों तक हुई। 2021 से 2025 तक सरकारी सोशल मीडिया चैनलों पर सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर 21 वेबिनार प्रसारित किए गए। कुल मिलाकर, एलएलएलएपी 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुँचा।.

फास्ट ट्रैक और अन्य न्यायालय

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पांच साल से ज्यादा समय से लंबित संपत्ति मामलों से संबंधित जघन्य अपराधों और दीवानी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) स्थापित किए गए थे-जहां 14वें वित्त आयोग ने 2015-20 के दौरान 1,800 एफटीसी की सिफारिश की थी, वहीं 30 जून, 2025 तक 865 एफटीसी कार्यरत हैं।

अक्टूबर 2019 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना ने गंभीर यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की स्थापना की, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के तहत पीड़ित भी शामिल हैं; 30 जून 2025 तक, 392 विशेष ढडउरड अदालतों सहित 725 एफटीएससी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यात्मक हैं और स्थापना के बाद से 3,34,213 मामलों का निपटारा किया है।

2019-20 में 767.25 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 474 करोड़ रुपये) के प्रारंभिक आवंटन के साथ शुरू हुई यह योजना दो बार बढ़ाई जा चुकी है, जिसमें नवीनतम विस्तार 31 मार्च, 2026 तक है, जिसमें 1,952.23 करोड़ रुपये (निर्भया फंड से 1,207.24 करोड़ रुपये) का परिव्यय है।

अन्य न्यायालय

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर की अदालतें हैं। मार्च 2025 तक, 488 ग्राम न्यायालय हैं, जो ग्रामीणों को समय पर, किफायती और कुशल न्याय तक पहुँच प्रदान करते हैं। ये जमीनी स्तर की अदालतें विवादों का त्वरित और स्थानीय स्तर पर समाधान करके ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाती हैं।

नारी अदालतें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत एक योजना है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इन अदालतों का उद्देश्य घरेलू हिंसा और अन्य लिंग-आधारित हिंसा से संबंधित मुद्दों को आपसी सहमति से बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से सुलझाना है।

इन अदालतों का नेतृत्व 7-9 महिलाएं करती हैं और ये महिलाओं को उनके संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और उन्हें कानूनी सहायता और अन्य सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का काम करती हैं।

नारी अदालत असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में चलाई जा रही है।

इसका पायलट परीक्षण किया जा रहा हैः

16 राज्यों अर्थात गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक की 10-10 ग्राम पंचायतें; और

2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 5-5 ग्राम पंचायतें।

पाकिस्तान ने 33 सालों बाद बनाया धांसू रिकॉर्ड, दक्षिण अफ्रीका के सामने रचा इतिहास

(जीएनएस)। कराची में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में 7 विकेट से शिकस्त दी। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। युवा बल्लेबाज सैम अय्यूब ने शानदार अर्धशतक जमाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 37।5 ओवर में महज 143 रन पर ढेर हो गई। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने 53 रन (70 गेंद, 6 चौके, 1 छक्का) की पारी खेली और टीम को संभालने की कोशिश की। वहीं, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस ने 39

रन बनाए। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा योगदान नहीं दे सका।

पाकिस्तान की ओर से अबफ्अफ अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज को 2-2 विकेट मिले। लक्ष्य छोटा था और पाकिस्तान ने इसे आसानी से हासिल कर लिया।

जवाबी पारी में सलामी बल्लेबाज फखर जमान बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन सैम अय्यूब ने शुरूआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने 77 रन (70 गेंद, 11 चौके, 1 छक्का) की आतिशी पारी खेली और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया।

बाबर आजम ने 27 रन जोड़े, जबकि विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। पाकिस्तान ने 25।1 ओवर में ही 144 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका की ओर से नांद्रे बर्गर और ब्योर्न फॉर्च्यून ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन वे पाकिस्तान की बल्लेबाजी को रोक नहीं सके।

पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैदान पर पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिछले पांच वनडे सीरीज में से चार में पाकिस्तान ने जीत दर्ज की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अबरार अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच और क्विंटन डी कॉक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

'सैयां नहीं तो भैया', सलमान खान ने सरेआम तान्या मित्तल को किया एक्सपोज

(जीएनएस)। टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों में है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी 'वीकेंड का वार' एपिसोड दर्शकों के लिए रोमांच और ड्रामा से भरपूर रहने वाला है। होस्ट सलमान खान ने इस बार कई प्रतियोगियों की क्लास लगाई, जिनमें तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी जैसे नाम शामिल हैं।

तान्या मित्तल के गेम प्लान का खुलासा

हाल ही में जारी प्रोमो वीडियो में सलमान खान तान्या मित्तल के गेम स्ट्रैटेजी का पदार्फाश करते दिखे। सलमान ने तान्या से कहा, "आपने जो नॉमिनेशन प्लान बनाया था, वो तो बिग बॉस ने ही बेकार कर दिया। आपने कहा था कि अमाल को 'भैया' बोलूंगी, लेकिन किसी को फर्क ही नहीं पड़ा।" इसके बाद सलमान ने मजाकिया अंदाज में कहा, "अब भैया से सैंया पर तो जा नहीं सकते। अगर यही आपका गेम प्लान था, तो वाह क्या गेम प्लान है आपका।" सलमान की यह बात सुनकर तान्या मित्तल चुप

रह गईं और उनके चेहरे के हावभाव बदल गए।

अमाल मलिक से दूरी पर भी उठे सवाल

दरअसल, शो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच पिछले कुछ समय से टकराव चल रहा है। तान्या ने घर में कई बार अमाल को नजरअंदाज किया और उनकी बातों का जवाब देने से भी इंकार कर दिया। हालांकि, जब ड्यूटीज बांटने का समय आया तो उन्होंने अमाल को 'भैया' कहकर संबोधित किया, जिससे घरवालों और दर्शकों दोनों का ध्यान उनकी ओर गया।

फरहाना और नीलम पर भी बरसे सलमान

तान्या के अलावा सलमान खान ने इस एपिसोड में फरहाना भट्ट और नीलम गिरी की भी जमकर क्लास लगाई सलमान ने दोनों से उनके व्यवहार और बयानों पर सवाल पूछे, जिससे माहौल और भी गरम हो गया।

दर्शकों में बढ़ी उत्सुकता

'वीकेंड का वार' का यह एपिसोड सोशल मीडिया पर रिलीज से पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है। फैंस यह जानने के लिए उत्साहित हैं कि सलमान खान आगे किन कंटेस्टेंट्स की पोल खोलने वाले हैं। एक बात तो तय है - इस हफ्ते का 'वीकेंड का वार' ड्रामा, हंसी और एक्सपोजर का पूरा पैकेज साबित होने वाला है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

प्रतापनगर यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के विश्वामित्री झ डभोई सेक्शन में स्थित प्रतापनगर स्टेशन पर यार्ड रिमोडलिंग कार्य हेतु इंजीनियरिंग ब्लॉक लिया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण 09 नवम्बर 2025 से 13 नवम्बर 2025 तक कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी। जिसका विवरण इस प्रकार हैः

पूर्णतः रद्द ट्रेनें

1.ट्रेन नं 69202 एकतानगर झ प्रतापनगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

2.ट्रेन नं 69203 प्रतापनगर – एकतानगर मेमू ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

3.ट्रेन नं 59122 छोटाउदैपुर – प्रतापनगर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

4.ट्रेन नं 59125 प्रतापनगर झ छोटाउदैपुर पैसेंजर ट्रेन 09 नवम्बर से 13 नवम्बर तक रद्द रहेगी

रेल यात्रियों से निवेदन है कि उपरोक्त बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करें। ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत आने वाले भावनगर परा स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैटरिंग स्टॉल का शुभारंभ दिनांक 08 नवम्बर, 2025 को किया गया।

इस स्टॉल का उद्घाटन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस अवसर पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के सचिव श्री एस. के. श्रीवास्तव, मंडल वाणिज्य निरीक्षक श्री तुषार शेख, मंडल परिचालन निरीक्षक श्री संजय सिंह, स्टेशन अधीक्षक श्री कृष्ण कुमार, रेलवे कर्मचारीगण एवं रेल यात्री उपस्थित रहे।

उद्घाटन अवसर पर श्री त्रिपाठी ने कैटरिंग स्टॉल के लाइसेंसी श्री विकास कुमार को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने श्री विकास कुमार को प्रोत्साहित करते हुए स्टॉल से खरीददारी भी की। उपस्थित अन्य कर्मचारियों एवं यात्रियों ने भी स्टॉल से खाने-पीने की वस्तुएं क्रय कर स्थानीय स्तर पर शुरू की गई इस सुविधा की सराहना की।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि इस स्टॉल के खुलने से भावनगर परा स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वच्छ, ताजा एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उचित दरों पर प्राप्त होगी, जिससे यात्री सुविधाओं में और अधिक वृद्धि होगी।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा की भावनगर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु स्टेशनों पर विभिन्न सेवाओं के विस्तार की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।

सीएक्यूएम ने 2025 में धान कटाई मौसम के दौरान पराली जलाने की समस्या को समाप्त करने के लिए हरियाणा एवं पंजाब द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की

आयोग ने पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल एवं समन्वित कार्रवाई का आ'ान किया

हरियाणा में प्रोत्साहन योजनाओं, प्रवर्तन एवं जमीनी स्तर पर मध्यवर्तन से पराली जलाने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है

(जीएनएस)।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने श्री राजेश वर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में पराली जलाने के मामलों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए पंजाब का क्षेत्रीय दौरा किया जिसका उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से फसल अवशेष प्रबंधन एवं प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित जमीनी स्थिति का आकलन करना था।

आयोग ने पटियाला जिले के राजपुरा में ताप विद्युत संयंत्र, संगरूर जिले के लहरागागा में संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र, मशीनरी के माध्यम से पराली का जमीनी स्तर पर प्रबंधन और बठिंडा जिले के लहरा मोहब्बत में ताप विद्युत संयंत्र का निरीक्षण किया। अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा ने लहरा मोहब्बत ताप विद्युत संयंत्र का निरीक्षण करते हुए इसकी खराब परिचालन स्थिति तथा निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों एवं वायु गुणवत्ता मानकों का पालन न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सीएक्यूएम अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर इनमें सुधार लाने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए गए तो आयोग संयंत्र को बंद करने का निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हो सकता है। निरीक्षण के दौरान, टीम के सामने पराली जलाने की छिटपुट घटनाएं सामने आयी।

दौरा पूरा करने के बाद, आयोग ने 07 नवंबर 2025 को पंजाब सरकार के साथ चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई का अवलोकन किया गया। समीक्षा बैठक

के दौरान आयोग को पता चला कि 15 सितंबर से 06 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान पंजाब में पराली जलाने के 3,284 मामले दर्ज किये गए, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 5,041 मामले दर्ज किये गए थे, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली सुधार को दशार्ता है। मुक्तसर और फाजिल्का जैसे कुछ जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है, जो चिंता का विषय है और इसमें राज्य को तत्काल मध्यवर्तन करने की आवश्यकता है। आयोग ने पाया कि पंजाब में सितंबर 2025 तक, चार ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) (पीएसपीसीएल के 2 टीपीपीः लेहरा और रोपड़; टीएसपीएल- मानसा और एनपीएल- एलएंडटी) ने कुल मिलाकर केवल 3.12 लाख मीट्रिक टन फसल अवशेष का ही सह-प्रज्वलन किया, जबकि 2025-26 के लिए 11.83 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

आयोग ने कहा कि पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए पंजाब में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अध्यक्ष ने पंजाब को आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए तुरंत अपने प्रयास में तेजी लाने और एक सशक्त सूचना एवं संचार अभियान चलाने का निर्देश दिया। आयोग ने धान की पराली के उपयोग हेतु फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनरी की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने और धान की पराली का उपयोग करने वाले संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्रों और अन्य उद्योगों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। आयोग ने जमीनी स्तर पर बेहतर प्रवर्तन एवं जवाबदेही तंत्र पर भी बल दिया। आयोग ने उन नोडल अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जिनके अंतर्गत आने वाले खेतों में आग लगने की ज्यादा घटनाएं हुई हैं।

इसके अलावा, हरियाणा में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य द्वारा की गई कार्रवाई का अवलोकन करते हुए, आयोग ने 07 नवंबर 2025 को चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक भी की। बैठक में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 15 सितंबर से 06 नवंबर 2025 की अवधि के दौरान, हरियाणा में पराली जलाने की 206 मामले दर्ज हुए, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान 888 मामले दर्ज हुए थे। मामलों में हुई कमी सक्रिय, प्रोत्साहन-आधारित एवं प्रवर्तन-संचालित दृष्टिकोण का परिणाम है। इसके अलावा, सीएक्यूएम ने कहा कि फसल अवशेषों के इन-सीटू और एक्स-सीटू प्रबंधन के लिए किसानों को दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों से उनके व्यवहार में बहुत सकारात्मक बदलाव आया है। आयोग ने इस बात पर बल दिया कि समन्वित प्रयासों से खेतों में आग लगने की घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

आयोग ने हरियाणा में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार अन्य प्रमुख क्षेत्रों की भी समीक्षा की, जिनमें वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक स्रोत, निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से उत्पन्न धूल, सड़क की धूल, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन आदि शामिल हैं तथा इन स्रोतों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयोग ने क्षेत्र में स्थायी फसल अवशेष प्रबंधन एवं स्वच्छ वायु उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेहतर समन्वय, कार्य योजनाओं का सही कार्यान्वयन एवं आयोग द्वारा जारी वैधानिक निर्देशों को सख्ती से लागू करने के महत्व को दोहराया।

एनएचपीसी ने मनाया 51वाँ स्थापना दिवस

(जीएनएस)।

सरकार का एक "नवरत्न" उद्यम एनएचपीसी लिमिटेड ने 7 नवंबर 2025 को अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने और अपने 51वें स्थापना दिवस का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। एनएचपीसी के फरीदाबाद स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विधुत स्टेशनों और परियोजनाओं में भव्य समारोह आयोजित किए गए। इस अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने भारतीय डाक द्वारा एनएचपीसी पर जारी "कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प" का विमोचन किया। मुख्य अतिथि ने एनएचपीसी की गौरवशाली 50 वर्षों की यात्रा और प्रमुख उपलब्धियों को दशार्ती "उपलब्धि पुस्तिका" का भी विमोचन किया।

एनएचपीसी के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में आयोजित समारोह में दीप प्रज्ज्वलित करने के बाद मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर, एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता, एनएचपीसी के निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी और स्वतंत्र निदेशकगण शामिल थे।

इससे पहले माननीय केंद्रीय

विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर का एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता ने पौधा और शॉल भेंट कर स्वागत किया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय विद्युत, आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, हरियाणा परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री सचिन किशोर, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) श्री उत्तम लाल, निदेशक (परियोजनाएं) श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (तकनीकी) श्री सुप्रकाश अधिकारी, निदेशक (वित्त) श्री महेश शर्मा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री संतोष कुमार और एनएचपीसी के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ।

इस समारोह में विद्युत मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा निदेशक, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों/विभागों के प्रतिनिधि, एनएचपीसी के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

एनएचपीसी की स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग ने एनएचपीसी के 12 प्रतिष्ठित बांधों और बैराजों को दशार्ते हुए एक कस्टमाइज्ड "माई स्टैम्प" जारी किया। ये संरचनाएँ इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के उल्लेखनीय उदाहरण हैं और राष्ट्र के लिए जलविद्युत के दोहन में एनएचपीसी की विशेषज्ञता का प्रतीक हैं।

पिछले 50 वर्षों में एनएचपीसी की उपलब्धियों को दशार्ती उपलब्धि पुस्तिका, आकर्षक तस्वीरों के माध्यम से संगठन के समृद्ध इतिहास, उल्लेखनीय उपलब्धियों, तकनीकी उत्कृष्टता और 1975 में अपनी स्थापना से लेकर आज तक राष्ट्र निर्माण के प्रति पाँच दशकों की अटूट प्रतिबद्धता को खूबसूरती से दशार्ती है।

माननीय मुख्य अतिथि ने समारोह को संबोधित करते हुए एनएचपीसी को उसके 51वें स्थापना दिवस और उसकी स्वर्णिम यात्रा के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि एनएचपीसी देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी उल्लेखनीय प्रगति के पाँच दशकों के दौरान, जलविद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी का असाधारण योगदान पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात रहा है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने का आ'ान किया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एनएचपीसी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसके लिए एनएचपीसी को अपनी विद्युत उत्पादन प्रक्रियाओं में नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करना होगा और तकनीकी नवाचारों को अपनाना होगा।

वाणिज्य विभाग ने दक्षता और स्वच्छ शासन के लिए विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया

(जीएनएस)।

भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 5.0 का सफलतापूर्वक समापन किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्य कुशलता में सुधार लाना और विभाग, उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और संबद्ध संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना था। इस पहल के माध्यम से, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने और कार्यस्थल प्रबंधन एवं स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए।

विभाग के नोडल अधिकारी और उसके क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विशेष अभियान 5.0 की प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी गई, जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निरंतर गति सुनिश्चित हुई। विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों एवं संगठनों के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी ने अभियान की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अभियान के दौरान, 88,385 फाइलों की समीक्षा की गई और 46,255 फाइलों को हटाया गया। कुल 277 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिनसे ई-कचरे और स्क्रैप के निपटान से लगभग 70 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, और इसके परिणामस्वरूप 36,005 वर्ग फुट कार्यालय स्थान भी मुक्त हुआ।

अभियान के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य प्रणलियों में मुंबई स्थित भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) मुख्यालय में व्यापक स्तर पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना; छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियाँ लगाना और शून्य कार्बन जोन का निर्माण; हरियाली विकास, बेहतर पार्किंग सुविधाओं और स्थान अनुकूलन के माध्यम से कार्यालय परिसर का संवर्धन; और मद्रास निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एमईपीजेड) परिसर के पास झील का पुनरुद्धार शामिल था। अन्य पहलों में डिजिटलीकरण और रिकॉर्ड प्रबंधन, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन, ई-कचरे पर जागरूकता अभियान और विद्युत उपकरणों का इन्वेंट्री प्रबंधन और लिफ्ट निरीक्षण शामिल थे।

विशेष अभियान 5.0 के तहत इन सामूहिक प्रयासों ने वाणिज्य विभाग के सभी कार्यालयों में स्वच्छता, दक्षता और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी की एक मजबूत संस्कृति को सुदृढ़ किया है। नवीनीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन, डिजिटलीकरण और ई-कचरा निपटान पर ध्यान केंद्रित करने के जरिये इस अभियान ने कार्यस्थल की स्वच्छता को बढ़ाया है और सुशासन एवं प्रशासनिक उत्कृष्टता के सरकार के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न

दोनों पक्षों ने शीघ्र, संतुलित और व्यापक व्यापार समझौते के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की

(जीएनएस)।

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चौथे दौर की वार्ता आज ऑकलैंड और रोटोरुआ में संपन्न हुई। दोनों पक्षों के बीच पांच दिनों तक रचनात्मक और दूरदर्शी चर्चा हुई।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री श्री टॉड मैक्ले ने इस दौर में हुई स्थिर प्रगति की सराहना की और एक आधुनिक, व्यापक और भविष्योन्मुखी एफटीए की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की

पुष्टि की।

दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं के व्यापार, आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग और उत्पत्ति के नियमों सहित प्रमुख क्षेत्रों में विस्तृत चर्चा की। इन चचाओं में आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने और एक पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने की साझा महत्वाकांक्षा परिलक्षित हुई जो लचीले, समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा दे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत वैश्विक समृद्धि और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं में योगदान देने वाली गहरी आर्थिक साझेदारियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों मंत्रियों ने कहा कि प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से व्यापार प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि, निवेश संबंधों में गहनता, आपूर्ति श्रृंखला की सुदृढ़ता और दोनों देशों के व्यवसायों के लिए बेहतर पूवार्नुमान और बाजार पहुँच सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन

डिजीलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ने वाली ट्रस्ट लेयर के रूप में काम करता है - जो सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और जवाबदेह डिजिटल गवर्नेंस को सक्षम बनाता हैः एस कृष्णन, सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

NeGD ने 'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया; सम्मेलन में डिजिटल ट्रस्ट और दक्षता की आधारशिला के रूप में डिजीलॉकर की भूमिका को दिखाया गया

सात राज्यों को 'डिजीलॉकर एक्सीलरेटर' के रूप में मान्यता दी गई - असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम को विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया

राज्यों और उद्योग भागीदारों ने शासन, शिक्षा और वित्त में

डिजीलॉकर के स्केलेबल उपयोग-मामलों को प्रदर्शित किया

(जीएनएस)।

इस सप्ताह नई दिल्ली में राष्ट्रीय डिजीलॉकर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका विषय था - 'डिजीलॉकर-सभी के लिए पेपरलेस एक्सेस को सक्षम बनाना'। इस सम्मेलन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रौद्योगिकी और वित्तीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और डिजिटल गवर्नेंस विशेषज्ञ शामिल हुए। सम्मेलन में पेपरलेस गवर्नेंस, समावेशी शिक्षा और सुरक्षित डिजिटल सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में डिजीलॉकर की परिवर्तनकारी भूमिका पर बल दिया गया, जो देश में हो रही डिजिटल ट्रस्ट क्रांति में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (ठीक्क्ष्) ने भारत मंडपम में इसका आयोजन किया। इस सम्मेलन ने सहयोगी मंच प्रदान किया ताकि इस बात पर चर्चा की जा सके और दिखाया जा सके कि डिजीलॉकर कैसे एक साधारण सुरक्षित दस्तावेज भंडारण सुविधा से सरकार, शिक्षा और उद्योग क्षेत्रों में विश्वास, सुविधा और दक्षता की आधारशिला के रूप में विकसित हो रहा है।

"भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला

नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के सहयोग से "भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग" पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का 6 और 7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में आयोजन किया

विकसित भारत 2047 के लिए जल सुरक्षा बढ़ाने हेतु उपचारित जल की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया

उपयोग को बढ़ाने के लिए समान मानकों को अपनाने पर सहमति बनी

शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में उपचारित जल के दोबारा इस्तेमाल को अपनाने की जरुरत पर बल दिया गया

डेटा सेंटर जैसी उभरती जरुरतों को पूरा करने के लिए उपचारित जल के उपयोग का सुझाव दिया गया

(जीएनएस)।

नीति आयोग ने कर्नाटक सरकार और बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के सहयोग से ,अपने राज्य सहायता मिशन के तहत 6-7 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में 'भारत में उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में नीति आयोग के माननीय सदस्य डॉ. विनोद के. पॉल और कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती (डॉ.) शालिनी रजनीश और 18 राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसमें थिंक टैंक, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकताओं, शिक्षाविदों, यूनिसेफ, दक्षिण भारत के लिए इजराइल सरकार के प्रतिनिधि, सिंगापुर जल संघ और ज्ञान साझेदारों के नीति विशेषज्ञों ने भाग लिया, ताकि कृषि, घरेलू गैर-पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए उपचारित जल के उपयोग को बढ़ाने में चुनौतियों, अवसरों और नवाचारों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

उभरते मीठे पानी के संकट के संदर्भ में, डॉ. पॉल ने विकसित भारत 2047 के लिए एक बेहतर दृष्टिकोणके लिए प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग की संभावनाओं का अधिकतम उपयोग करने की जरुरत पर बल दिया, पुनः उपयोग पर राज्य स्तरीय नीतियों की जरुरत और विभिन्न उपयोगों के लिए लागू करने योग्य सामान्य मानक विकसित करने, डेटा सेंटर जैसे उभरते जल आवश्यकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त जल के पुनः उपयोग को एकीकृत करने, पुनः उपयोग के स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं और व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने से, जल सुरक्षा बेहतर करने, मीठे पानी पर निर्भरता कम करने, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने और संसाधन चक्रीयता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए एक बदलावकारी मौका मिलता है। उन्होंने उपचारित जल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

कर्नाटक सरकार की मुख्य सचिव ने शहर में 2024 की संकटकालीन स्थिति में राज्य द्वारा की गई अग्रणी पहलों का उल्लेख किया, जैसे झीलों के पुनरुद्धार के लिए प्रयुक्त जल का पुनः उपयोग और औद्योगिक माँग को पूरा करना। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से देश और राज्य के लिए रणनीतिक विचारों के साथ आगे आने की अपील की, ताकि पुनः उपयोग क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें।

कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने 2030 तक मजबूत राज्य-स्तरीय नीतियों और बहु-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए स्पष्ट साझा मानकों की जरुरतों पर जोर दिया। इसके अलावा प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड अवसंरचना और उपयोगकर्ता के स्वास्थ्य के नजरिए से वास्तविक समय गुणवत्ता निगरानी प्रणालियाँ और उपयोगिताओं के भीतर क्षमता निर्माण की स्थापना के महत्व पर भी जोर दिया गया। विकेन्द्रीकृत उपचार प्रणालियों के लिए लागत-प्रभावी तकनीकों और टिकाऊ संचालन तथा रखरखाव ढाँचों की जरुरत को उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए ठोस कारकों के रूप में पहचाना गया।

इस दौरान वरिष्ठ राज्य पदाधिकारियों द्वारा कई राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को भी पेश किया गया। गुजरात के स्केलेबल पुनः उपयोग मॉडल, दिल्ली की राजस्व-उत्पादक पहल, पुनः उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए इंदौर का बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण, कर्नाटक की एकीकृत ग्रामीण-औद्योगिक पुनः उपयोग प्रणालियाँ, औद्योगिक उपयोग के लिए तमिलनाडु का तृतीयक उपचारित जल और महाराष्ट्र के प्रौद्योगिकी-सक्षम ग्रे वाटर समाधान, ये सभी अन्य राज्यों के लिए पुनः उपयोग को बढ़ाने की संभावनाएँ प्रदान करते हैं। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र के दृष्टिकोण साझा किए गए, जिनमें भारत की एक वृत्ताकार जल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव को रफ्तार देने के लिए सहयोगी व्यावसायिक मॉडल, नवोन्मेषी वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व को भी रेखांकित किया गया।

कार्यशाला का समापन 7 नवंबर को बीडब्ल्यूएसएसबी के केएंडसी वैली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कब्बन पार्क ट्रीटमेंट प्लांट के क्षेत्रीय दौरे के साथ हुआ, जहाँ राज्यों के प्रतिभागियों ने उपचार और पुनः उपयोग की उन्नत तकनीकों का अवलोकन किया।

कर्नाटक के शहरी विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री तुषार गिरि नाथ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में अमृत विभाग की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक श्रीमती डी. थारा, ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम के मुख्य आयुक्त श्री महेश्वर राव, नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक श्री युगल जोशी और बेंगलुरु जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. वी. राम प्रसाद मनोहर ने कार्यशाला में विचार-विमर्श में भाग लिया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरूआत की

वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं: प्रधानमंत्री

एक विकसित भारत के लिए अपने संसाधन बढ़ाने के मिशन की भारत की शुरूआत, उस यात्रा में ये ट्रेनें मील का पत्थर साबित होंगी: प्रधानमंत्री

पवित्र तीर्थस्थल अब वंदे भारत नेटवर्क से जोड़े जा रहे हैं, जो भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा का संगम हैं; यह विरासत शहरों को राष्ट्रीय प्रगति के प्रतीक में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

भारत के आधुनिक रेल बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री मोदी ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी के सभी परिवारों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देव दीपावली के दौरान मनाए गए असाधारण उत्सवों का जिक्र किया और कहा कि आज का दिन भी एक शुभ अवसर है। उन्होंने विकास के इस उत्सव के लिए सभी को शुभकामनाएं दीं।

यह देखते हुए कि दुनिया के विकसित देशों में, आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक मजबूत बुनियादी ढांचा रहा है, श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जिन भी देशों ने महत्वपूर्ण प्रगति और विकास हासिल किया है, वहां बुनियादी ढांचे की उन्नति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत पर्व-2025, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता नगर : 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'

एकता नगर के प्रकाश पर्व में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का प्रतीक 'ग्रीन ट्री' बना आकर्षण का केन्द्र

भारत पर्व-2025 के थीम पैवेलियन का मुख्य आकर्षण 'ग्रीन ट्री' विकास, टेक्नोलॉजी तथा एकता का झिलमिलाता प्रतीक

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को उजागर करने वाला 'ग्रीन ट्री' प्रकाश एवं प्रगति का अनूठा प्रदर्शन

गांधीनगर, 08 नवंबर :सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात के एकता नगर में भारत सरकार तथा गुजरात सरकार के सहयोग से विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के परिसर में भव्य भारत पर्व-2025 का आयोजन हुआ है। यह पहली बार है कि भारत पर्व दिल्ली से बाहर आयोजित हो रहा है और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में गुजरात ने इस पर्व को भव्यता दी है। इस पर्व के दौरान देश की विविधता में एकता का प्रतीक दशार्ने वाले सांस्कृतिक, टेक्नोलॉजिकल तथा देशभक्ति से प्रेरित कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है।

भारत पर्व-2025 के थीम पैवेलियन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुए विभिन्न राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तथा विकास के प्रतीकों को अनूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पैवेलियन का मुख्य आकर्षण 'ग्रीन ट्री' है, जो विकसित भारत के सपने को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त करता है। प्रकाशित इन्स्टॉलेशन के रूप में खड़े इस ग्रीन ट्री द्वारा भारत के सर्वांगीण विकास की दिशा एवं प्रगति का दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ है। इस दृश्यावली ने देशभक्ति, आर्ट तथा टेक्नोलॉजी का अद्भुत संगम सृजित किया है; जो देश-विदेश के पर्यटकों को अद्भुत अनुभूति कराता है।

'ग्रीन ट्री' इन्स्टॉलेशन में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी विजन के तहत साकार हुए राष्ट्रीय स्तर के माइल स्टोन प्रोजेक्ट्स को प्रकाशित ढंग से प्रस्तुत किया गया है; जैसे कि सूरत डायमंड बोर्स, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तेजस फाइटर जेट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑपरेशन सिंदूर, लक्षद्वीप विकास, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, स्टैच्यू ऑफ इक्वैलिटी, महाकुंभ-2025, आईएनएस विक्रांत, सोनमर्ग टनल, विझिंजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तथा अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स। ये सभी प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने वाले प्रतीकात्मक चरणों के रूप में झिलमिलाते हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में आईआईएसएफ 2025 का पूर्वावलोकन समारोह आयोजित किया गया

(जीएनएस)।

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में आज भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव (आईआईएसएफ) 2025 के 11वें संस्करण का पूर्वावलोकन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के साथ आईआईएसएफ 2025 के समारोहों की शुरूआत हुई, जो 6 से 9 दिसम्बर 2025 तक पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम की शुरूआत पंजाब विश्वविद्यालय के गीत के साथ हुई, जिसके बाद पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह और सरस्वती वंदना के साथ ज्ञान और ज्ञानोदय की भावना का आ'ान किया गया।

इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में, डॉ. रविचंद्रन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जहाँ ईएसटीआईसी ऊपर से नीचे तक के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, वहीं आईआईएसएफ नीचे से ऊपर की ओर आंदोलन लाता है, जो विज्ञान को लोगों तक ले जाता है। उन्होंने युवा मन में जिज्ञासा और उत्साह को पोषित करने के महत्व पर बल दिया, और कहा कि विज्ञान का जश्न इस तरह से मनाना आवश्यक है जो अगली पीढ़ी को नवाचार और अन्वेषण के लिए प्रेरित करे।

भारत के विकासात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए, डॉ. रविचंद्रन ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और इन क्षेत्रों को मजबूत किए बिना, राष्ट्र अपने वांछित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकता है। उन्होंने वैज्ञानिक समझ को रचनात्मकता और प्रगति के उत्सव में बदलने के उद्देश्य से एक जन-केन्द्रित पहल के रूप में आईआईएसएफ की भूमिका पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में विभा के राष्ट्रीय आयोजन सचिव डॉ. शिव कुमार शर्मा, आईआईटीएम पुणे के निदेशक डॉ. ए. सूर्य चंद्र राव, पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. रेणु विग, पंजाब विश्वविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की निदेशक डॉ. मीनाक्षी गोयल और पंजाब विश्वविद्यालय में आईआईएसएफ 2025 के समन्वयक प्रो. गौरव वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

आयोजन समिति ने सम्मान स्वरूप गणमान्य व्यक्तियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। अपने स्वागत भाषण में प्रो. रेणु विग ने पूर्वावलोकन समारोह की मेजबानी पर गर्व व्यक्त किया और वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉ. शिव कुमार शर्मा और डॉ. ए. सूर्य चंद्र राव ने विज्ञान सूचना के महत्व और देश भर में वैज्ञानिक सोच के निर्माण में युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।

पूर्वावलोकन- भारतीय नौसेना तिरुवनंतपुरम में भव्य परिचालन प्रदर्शन के साथ नौसेना दिवस 2025 मनाएगी

(जीएनएस)।

भारतीय नौसेना 04 दिसंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के शंगुमुघम समुद्र तट पर एक शानदार परिचालन प्रदर्शन के साथ नौसेना दिवस 2025 मनाएगी।

यह भारतीय नौसेना के प्रमुख नौसेना स्टेशनों के अलावा किसी अन्य स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश का एक सिलसिला है। इससे पहले, यह ओडिशा के पुरी और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम नागरिकों को भारतीय नौसेना के बहु डोमेन संचालन के विभिन्न पहलुओं को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। ऑपरेशनल प्रदर्शन भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म और महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) के व्यापक विजन द्वारा निर्देशित हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार' के रूप में इसके संकल्प को प्रदर्शित करेगा। यह कार्यक्रम नौसेना की दुर्जेय लड़ाकू क्षमताओं, तकनीकी उत्कृष्टता और परिचालन तत्परता को जीवंत करेगा, साथ ही देश की बढ़ती समुद्री ताकत और आत्मनिर्भरता को भी दर्शाएगा।

इस ऑपरेशनल प्रदर्शन में अग्रिम पंक्ति के प्लेटफार्मों द्वारा समन्वित युद्धाभ्यास प्रदर्शित किए जाएंगे, जो नौसेना की समुद्री क्षेत्र में शक्ति और सटीकता प्रदान करने की क्षमता का प्रतीक होगा। यह कार्यक्रम सतह, उप-सतही और हवाई संपत्तियों के निर्बाध सहयोग को उजागर करेगा, जो भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए नौसेना की तैयारी को दशार्ता है।

आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दशार्ते हुए, इस प्रदर्शन में रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व करने वाली कई स्वदेशी निर्मित संपत्तियां प्रदर्शित की जाएंगी।

ये मंच 'मेक इन इंडिया' के तहत नौसेना के निरंतर प्रयासों को मूर्त रूप देते हैं, जिससे एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत और भविष्य के लिए तैयार समुद्री बल का निर्माण होता है। यह समारोह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदर्शित नौसेना की तैयारियों और निवारक क्षमता को भी उजागर करेगा, जो सटीकता, गति और प्रभुत्व के साथ हमला करने की उसकी क्षमता की पुष्टि करता है। यह प्रदर्शन भारतीय नौसेना के उन पुरुषों और महिलाओं के व्यावसायिकता, अनुशासन और साहस को श्रद्धांजलि है जो देश की संप्रभुता और समुद्री हितों की रक्षा करते हैं। नौसेना दिवस 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है, जिसने दुश्मन की नौसेना और तटीय सुरक्षा को करारा झटका दिया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, भारतीय नौसेना की मिसाइल नौकाओं ने कराची बंदरगाह पर एक साहसिक हमला किया।

भारत ने ब्राजील के बेलेम में यूएनएफसीसीसी कॉप-30 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में समतामूलक जलवायु कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

विकसित देशों को उत्सर्जन में कमी लाने में तेजी लानी चाहिए और वादा किया गया, पर्याप्त और पूर्वानुमानित समर्थन प्रदान करना चाहिए: भारत

भारत ने उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण हेतु स्थायी सुविधा (टीएफएफएफ) स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत किया, पर्यवेक्षक के रूप में इस पहल में शामिल हुआ

(जीएनएस)।

07 नवम्बर, 2025 को कॉप-30 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए, ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया ने समानता, राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु कार्रवाई के प्रति देश की निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के 30वें पक्ष सम्मेलन (कॉप-30) का आयोजन 10 से 21 नवंबर, 2025 तक ब्राजील के बेलेम में हो रहा है।

भारत ने पेरिस समझौते की 10वीं वर्षगांठ पर कॉप-30 की मेजबानी के लिए ब्राजील का आभार व्यक्त किया और रियो शिखर सम्मेलन की 33 वर्षों की विरासत को याद किया। भारत के बयान में कहा गया कि यह ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया पर विचार करने का एक अवसर है। यह रियो शिखर सम्मेलन की विरासत का जश्न मनाने का भी अवसर है, जहाँ समता और सीबीडीआर-आरसी के सिद्धांतों को अपनाया गया था, जिसने पेरिस समझौते सहित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था की नींव रखी।

भारत ने उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए सामूहिक और सतत वैश्विक कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे मान्यता देते हुए उष्णकटिबंधीय वनों के लिए सदैव सुविधा (टीएफएफएफ) स्थापित करने की ब्राजील की पहल का स्वागत किया और पर्यवेक्षक के रूप में इस सुविधा में शामिल हो गया।

भारत सरकार ने लघु मत्स्य पालन, मत्स्य सहकारी समितियों और एफएफपीओ को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं

"विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग" के लिए नियम अधिसूचित किए गए

(जीएनएस)।

भारत सरकार ने एक समृद्ध और समावेशी समुद्री अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, 04.11.2025 को "विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मत्स्य पालन के टिकाऊ उपयोग" के नियमों को अधिसूचित किया है। भारत के समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता को उजागर करने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता से प्रेरित यह पहल, बजट 2025-26 की उस घोषणा को पूरा करती है जिसमें अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय ईईजेड और विशाल सागरों से टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए एक सक्षम ढाँचे की परिकल्पना की गई थी।

सहकारिता और समुदाय-आधारित मॉडलों का सशक्तिकरण

ये नियम गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्यों को करने और प्रबंधन के लिए मछुआरा सहकारी समितियों और मत्स्यपालक उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को प्राथमिकता देते हैं। ईईजेड नियम न केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि मूल्यवर्धन, पता लगाने की क्षमता और प्रमाणन पर जोर देकर समुद्री खाद्य निर्यात को बढ़ाने में भी योगदान देंगे। इस पहल से आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा मातृ-और-शिशु पोत अवधारणा की शुरूआत के माध्यम से भारतीय समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए नए क्षितिज खुलने की संभावना है।

तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के बीच में ट्रांसशिपमेंट की अनुमति मिलती है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों में, जो भारत के ईईजेड क्षेत्र का 49 प्रतिशत हिस्सा हैं, विशाल और छोटे जहाजों के उपयोग से उच्च गुणवत्ता वाली मछली के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

व्यापक सहायता और क्षमता निर्माण

सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दौरों और ब्रांडिंग और निर्यात सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों/एफएफपीओ को व्यापक सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) जैसी प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत आसान और किफायती ऋण तक पहुँच को सुगम बनाया जाएगा।

हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाना, टिकाऊ मत्स्य पालन और समुद्री कृषि को प्रोत्साहन देना

ईईजेड नियम समुद्री इकोसिस्टम की रक्षा और मछली पकड़ने के समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए एलईडी लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग और बुल ट्रॉलिंग जैसी हानिकारक मछली पकड़ने की प्रथाओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, मछली प्रजातियों के लिए एक न्यूनतम कानूनी आकार भी निर्धारित किया जाएगा और घटते मछली भंडार को बहाल करने के लिए राज्य सरकारों सहित हितधारकों के परामर्श से मत्स्य प्रबंधन योजनाएँ विकसित की जाएंगी। पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किए बिना उत्पादन बढ़ाते हुए निकटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने के दबाव को कम करने के लिए समुद्री पिंजरे की खेती और समुद्री शैवाल की खेती जैसी समुद्री कृषि प्रथाओं को भी वैकल्पिक आजीविका के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ये उपाय विशेष रूप से छोटे पैमाने के मछुआरों और उनकी सहकारी समितियों को लाभान्वित करेंगे, जिससे उन्हें गहरे समुद्र के संसाधनों तक पहुँचने, अधिक आय अर्जित करने और टूना जैसी उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को वैश्विक बाजारों में निर्यात करने में सहायता मिलेगी।

ईईजेड संचालन के लिए डिजिटल और पारदर्शी एक्सेस पास व्यवस्था

ईईजेड नियमों के अंतर्गत, मशीनीकृत और बड़े आकार के मोटर चालित जहाजों के लिए एक्सेस पास आवश्यक है, जिसे ऑनलाइन रीएएलसीराफ्ट पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। मोटर चालित या गैर-मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जहाजों का संचालन करने वाले पारंपरिक और

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली के यशोभूमि में राष्ट्रीय शहरी कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया

डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) अर्बन इन्वेस्ट विंडो (यूआईडब्ल्यूआईएन) सहित प्रमुख पहलों को लॉन्च किया

डीआरएपी 80 प्रतिशत विरासत अपशिष्ट के 214 उच्च प्रभाव वाले स्थलों को प्राथमिकता देगा

'प्रत्येक शहर और प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए... परिसंपत्ति का निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका रखरखाव और प्रबंधन कहीं अधिक महत्वपूर्ण है': श्री मनोहर लाल

(जीएनएस)।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया।

यह दो दिवसीय सम्मेलन नीति निमार्ताओं, शहरी योजनाकारों, विशेषज्ञों और हितधारकों सहित विभिन्न कार्य क्षेत्रों के 2500 से अधिक प्रतिभागियों को छह विषयगत क्षेत्रों में गहन विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से 'सतत शहरी विकास और शासन' थीम पर विचार-विमर्श करने के लिए एकजुट करता है।

विवरण देखने और सत्रों को लाइव देखने के लिए यहां क्लिक करें

'विकसित भारत सिटी' प्रदर्शनी

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर 'विकसित भारत सिटी' प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो वास्तविक रूप से विकसित, जीवंत, समावेशी, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार भारतीय शहर के विजन को जीवंत करती है। यह प्रदर्शनी भारतीय शहरों में लागू किए जा रहे अभिनव शहरी नियोजन मॉडल, स्मार्ट प्रौद्योगिकीयों और लोक-केंद्रित अवसंरचना को प्रदर्शित करती है।

श्री धर का संबोधन

लोक नीति विशेषज्ञ श्री देवाशीष धर ने भारत के शहरी अवसरों की पड़ताल करते हुए, इस बात पर बल दिया कि शहर समृद्धि के स्थानिक इंजन हैं, जहां लोग विकास, अवसर और स्वतंत्रता की खोज में प्रवास करते हैं। उन्होंने शहरों को "श्रम बाजार" बताया, जो भीड़भाड़ और लोगों के समूहों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा और मूल डीपीआई - "वांछित सार्वजनिक अवसंरचना" के रूप में, जिस पर समृद्धि का निर्माण होता है, से आकार लेते हैं।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव का वक्तव्य

आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने सतत शहरी विकास को साकार करने में समन्वित शासन और संस्थागत शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन शहरी नेताओं और विशेषज्ञों को अपने अनुभव साझा करने और भारत के शहरी भविष्य के लिए मिलकर समाधान तैयार करने हेतु एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है।

आवास एवं शहरी कार्य सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह आयोजन शहरों को अधिक किफायती, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के सामूहिक प्रयास का प्रतिबिंब है। माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, विकसित भारत के लिए टीम अर्बन के शुभारंभ के अवसर पर, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सहयोग और साझा जवाबदेही की शक्ति पर बल दिया। यह कॉन्क्लेव वार्षिक राष्ट्रीय शहरी संवाद का उद्घाटन संस्करण है, जो अर्बन एजेंडा 2047 को अर्जित करने के लिए स्पष्ट मार्ग और कार्यान्वयन योग्य योजनाओं की पहचान करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने उद्घाटन सत्र के दौरान, निम्नलिखित का शुभारंभ किया:

1. डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) का शुभारंभ

केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने डंपसाइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम (डीआरएपी) का भी शुभारंभ किया। यह एक वर्ष चलने वाला, मिशन-मोड कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य शहरी भारत में शेष डंपसाइटों के उपचार को फास्ट ट्रैक करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक और अवसंरचना विकास के लिए मूल्यवान शहरी भूमि का पुनर्ग्रहण करना है, जिससे सितंबर 2026 तक "लक्ष्य जीरो डंपसाइट" अर्जित करने के भारत के विजन को आगे बढ़ाया जा सके।

वर्तमान में, 1,428 स्थलों का सुधार कार्य जारी है और लगभग 80 प्रतिशत विरासत अपशिष्ट 202 शहरी स्थानीय निकायों के 214 स्थलों पर केंद्रित है। डीआरएपी इन उच्च-प्रभाव वाले स्थानों को प्राथमिकता देगा और लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन विरासत अपशिष्ट को कवर करेगा।

मेगा कैंप के दौरान 200 से अधिक डीएलसी तैयार किए गए

पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के माध्यम से डिजिटल सशक्तिकरण पर संतोष व्यक्त किया

फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक, डीएलसी जेनरेशन को 'कभी भी कहीं भी' सक्षम करने में बेहद फायदेमंद है

(जीएनएस)।

श्री वी. श्रीनिवास, सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू), ने राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 के अंतर्गत 7 नवंबर, 2025 को संसद मार्ग शाखा, दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा आयोजित मेगा कैंप का उद्घाटन किया और पेंशनभोगियों को संबोधित किया। उन्होंने पेंशनभोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के डिजिटल तरीकों की शुरूआत के माध्यम से की गई पहल पर प्रकाश डाला, जिससे उनके जीवन में काफी आसानी हुई है और यह वृद्ध/बीमार पेंशनभोगियों के लिए बेहद लाभदायक है। पंजाब नेशनल बैंक देश भर के 39 शहरों में 185 स्थानों पर कैंप आयोजित कर रहा है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों (पेंशन संवितरण बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, पेंशनभोगी कल्याण संघ, सीजीडीए, ईपीएफओ, दूरसंचार विभाग, रेलवे, यूआईडीएआई और एमईआईटीवाई) के सहयोग से 1 से 30 नवंबर, 2025 तक राष्ट्रव्यापी डीएलसी अभियान 4.0 चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। इस वर्ष अब तक 67.94 लाख डीएलसी तैयार किए गए हैं, जिनमें से 40.42 लाख फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हैं। 1 से 5 नवंबर तक 5 दिनों में 25.60 लाख डीएलसी तैयार किए गए हैं, जिनमें से 15.62 लाख (61 प्रतिशत) फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से हैं। 90 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के 37000 से अधिक डीएलसी और 100 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के 985 डीएलसी तैयार किए गए।

मेगा कैंप के दौरान पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने हेतु चेहरे से प्रमाणीकरण किया गया। डिजिटल माध्यमों से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, विशेष रूप से चेहरे से प्रमाणीकरण तकनीक, जो 'कभी भी, कहीं भी' जीवन प्रमाण पत्र बनाने में सक्षम बनाती है, पर इन डीएलसी निमार्णों के दौरान प्रकाश डाला गया।

मेगा कैंप के दौरान, सचिव (पी एंड पीडब्ल्यू) श्री वी. श्रीनिवास ने पेंशनभोगियों से बातचीत की। पेंशनभोगियों ने पेंशनभोगियों की सुविधा और जीवन को आसान बनाने के लिए विकसित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, विशेष रूप से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक, पर अपनी अपार संतुष्टि और प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि यह स्मार्ट फोन के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इससे पेंशनभोगियों द्वारा डीएलसी जमा करना आसान हो जाता है और यह विशेष रूप से वृद्ध/बीमार पेंशनभोगियों के लिए उपयोगी है, जिन्हें किसी बैंक या पेंशन वितरण प्राधिकरण के पास बार-बार नहीं जाना पड़ता।